International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

लघु ऋण का ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्त्व

Bablee
Lecturer in Commerce
Govt. Sr. Sec. School
Chiri, Rohtak
Mob. : 9050192786

शोध–आलेख सारः लघु ऋण की ग्रामीण क्षेत्र के विकास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो इसकी यह मिली की सेठ–साहूकारी प्रथा का अन्त अपने अन्तिम छोर पर है। विभिन्न अध्ययनों द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि पहले महाजन व बड़े–बड़े सेठ –साहूकारों से ऋण लेने की दर 62 प्रतिशत थी। लेकिन लघु ऋण व्यवस्था की वजह से यह प्रतिशत अब बहुत ही कम होता जा रहा है अब यह 10 प्रतिशत ही है। युनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमेटी 2005 की रिर्पोट के अनुसार, 'वित्तिय सेवाऐं गरीबों के लिए बहुत आवश्यक है। विश्व स्तर पर भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि लघु ऋण व्यवस्था पिछले कई दशकों से गरीबी को उखाड़ फेंकने हेतु बहुत महत्त्वपूर्ण हथियार है, लघु ऋण व्यवस्था का गरीबों के जीवन में बहुत महत्त्व है। अतः इसके द्वारा 2015 तक 50 फीसदी गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा था। लघु ऋण व्यवस्था ही लघु वित्त व्यवस्था कहलाती है। लघु वित्तिय कार्यक्रम अधिकतर स्थानीय आधार पर संचालित किए जाते हैं लघु ऋण सुविधा देकर अभावग्रस्त लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की पूरी कोशिश की जाती है। लघु वित्तिय सेवाओं का आकार छोटो होता है अर्थात् ऋण की राशी बहुत छोटी होती है तथा लघु ऋण सेवाऐं प्राप्त करने वाले तो गरीब व बेहद गरीब होते है।

मुख्य शब्द : लघु ऋण, प्राथमिक शाखा, ग्रामीण विकास, जनगणना, विकासशील अर्थ व्यवस्था, लघु वित्तिय कार्यक्रम, विकासशील अर्थव्यवस्था, लघु वित, लघु ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, जनगणना, प्राथमिक साख, ग्रामीण विकास

अनुसंधान क्रियाविधिः इस शोध आलेख की रचना हेतु हमने विभिन्न literature का पुनर्निरिक्षण किया है तथा इसके लिए गौण आंकड़ों का प्रयोग किया जिनका स्रोत विभिन्न शोध आलेख, शैक्षणिक लेख, विभिन्न व्यवसायिक पत्र–पत्रिकाऐं, भारतीय अर्थव्यवस्था, वार्षिक अंक, बैंकिग topics in different books, internet, वेबसाईस का पुनर्निरिक्षण किया और लघु वित्त की ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में भूमिका को जाना। ये स्रोत मेरे शोध आलेख को तैयार करने में काफी सहायक सिद्ध हुए।

शोध आलेख परिचयः हम सब जानते है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है वर्ष 2011 की जनगणना पर नजर डालें तो पता चलता है भारत की 68.8 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में वास करती है और कृषि व लघु उद्योग ही इनकी जीविका का प्रमुख साधन होता है अर्थात् इनका जीवन कृषि व लघु कुटीर उद्योगों पर निर्भर होता है। अगर यह कहें कि ग्रामीण जनता का आधार सतम्भ कृषि है तो यह गलत नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से 54 प्रतिशत लोग रोजगार में लगे हुए हैं, अतः कृषि व लघु उद्योग से होने वाले लाभ व हानियों का प्रभाव सीधे–सीधे ग्रामीण लोगों पर पड़ता है और यह भी सर्वविदित है कि कृषि मानसून पर पूरी तरह निर्भर करती है। मानसून के कम या ज्यादा होने के अनुरूप ही फसल का उत्पादन कम या ज्यादा होता है। जिस वर्ष मानसून कम होती है उस वर्ष किसानों की फसल खराब हो जाती है और ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेने की जरूरत पड़ती है। प्राचीन समय से आज तक ग्रामीणों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजन व सेठ साहूकारों पर निर्भर होना पड़ता है। सेठ–साहूकारों के ऋण देने की ब्याज दर बहुत ऊँची होती है, जिसका ब्याज पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतान करने पर भी पूर्णत नहीं चुका पाते। सम्पूर्ण विकास के पैमानों पर कार्य करने के बाद भी गरीबी अपने पूर्ण अस्तित्व में दिखाई देती है। जो व्यक्ति को खास करके ग्रामीणों को आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक अभावों के साथ जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। ग्रामीण लोगों की छोटी–छोटी जरूरतों को पूरा करने के

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

लिए लघु ऋण / लघु वित्त का कॉन्सेप्ट सामने आया। विकास की नई–नई अवधारणाओं में उद्यमिता से सम्बन्धित नीतियाँ या लघुवित्तिय संस्थाऐं आवश्यक अंग के रूप में सामने आई है। यहाँ तक भी माना जाने लगा है कि व्यापार व उद्यमों के द्वारा गरीब ग्रामीणों के भविष्य को सुनहरा बनाया जा सकता है। युनाईटेड नेशन वर्ल्ड समिति 2005 में कहा गया है कि ''वित्तिय सेवाऐं गरीबों के लिए अति आवश्यक है।'' जिसमें लघु वित्त व लघु ऋण जैसी नीतियों को पोषित किया गया है। सर्वप्रथम लघु वित्तीय सेवाओं के महत्त्व को समझने वाले व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता जटगांव यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर मोहम्मद युनुस थे उन्होंने 1976 में अकाल के दौरान गरीबी के खिलाफ संघर्ष किया और स्पष्ट रूप से उनका मानना है कि –''अगर गरीब लोगों को सही व उचित शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराया जाऐ तो लाखों लोग अपनी छोटी–छोटी व्यवसायिक गतिविधियों के माध्यम से एक चमत्कारिक विकास कर सकते हैं। इसी सोच के आधार पर उन्होंने गरीबी को हटाने के लिए पहला ऋण स्वयं दिया जो 27 डॉलर था और ग्रामीण बैंक स्थापित किया। जो उन निर्धन व संसाधनहीन लोगों को ऋण उपलब्ध कराता था, जिन्हें आमतौर पर बैंक ऋण नहीं देते थे। विश्व में लघु वित्त व्यवस्था का प्रारम्भ सन् 1970 में हुआ लेकिन भारत में यह व्यवस्था सन् 1992 से शुरू हुई। हम जानते है कि लघु वित्त एक प्रकार से लघु ऋण की राशी ही है। जो गरीब कृषकों व ग्रामीणों को उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए उपलब्ध करायी जाती है। लघु ऋण के अंतर्गत लगभग पचास हजार रूपये तक का ऋण बिना किसी जमानत के दिया जाता है उनसठ जी (59 G) नेशनल सेम्पल सर्वे के अनुसार आज भी 51 प्रतिशत ग्रामीण लोग ऋण सुविधा से वंचित है, अतः लघु वित्त का मुख्य उद्देश्य इन लोगों को उनकी आवश्यकताऐं पूरी करने के लिए लघु ऋण उपलब्ध कराना है।

ग्रामीणों की निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लघु वित्त / लघु ऋण दिया जाता है।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

1. चिकित्सा सुविधा के लिए
2. पशुओं के लिए चारा खरीदने के लिए
3. विवाह, मुंडन आदि संस्कारों को सम्पन्न करने हेतु
4. शिक्षा प्राप्त करने के लिए
5. अनाज खरीदने के लिए
6. त्यौहार मनाने के लिए
7. खाद्य व बीज खरीदने के लिए

ग्रामीण लोग पुराने समय से ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपनी सम्पत्ति (पशुधन, भूमि, जेवर) को स्थानीय महाजनों व सेठ–साहूकारों के पास जमानत के रूप में गिरवी रखते थे तथा इसके बदले ऋण के रूप में कुछ राशी प्राप्त करते थे। लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्य पूर्ण बात यह होती थी कि ऋण की कई गुना राशी प्राप्त करने के बाद भी सेठ–साहूकार ऋण को चुकता नहीं मानता था और अन्ततः जमानत के रूप में रखी सम्पत्ति भी साहूकार महाजन ही जब्त कर लेता था यह कहकर की मेरा सूद अभी बाकी है। इस प्रकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण आजीवन सेठ–साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे। यहाँ तक की ऋण प्राप्तकर्ता की अगली पीढ़ी भी उसके चंगुल से निकल पाने में असमर्थ होती थी।

लघु ऋण की विशेषताऐं–

1. लघु वित्त व्यवस्था की शुरूआत नब्बे की दशक से हुई।
2. गरीब ग्रामीणों को आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु जो छोटी–छोटी राशी वित्त के रूप में उपलब्ध करायी जाती है, यह राशी ही लघु ऋण है।
3. लघु ऋण का सम्बन्ध बीमा व बचत से भी है।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

4. लघु वित्त / ऋण एक ऐसी वित्त व्यवस्था है जो अत्यधिक गरीब ग्रामीणों को बिना किसी सम्पत्ति के गिरवी रखे छोटे ऋण के रूप में पैसा उपलब्ध कराती है।

5. लघु वित्त व्यवस्था के अनतर्गत कृषि के लिए भी छोटी–राशी का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कृषक खाद–बीज व पशुओं के लिए चारा आदि खरीद सकें और अपनी कृषि व कृषि से सम्बन्धित गतिविधियों को संचालित कर सकें।

6. लघु वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत लघु व कुटीर उद्योग गतिविधियों के लिए भी पैसा उपलब्ध कराया जाता है।

सामान्यतः गाँवों के गरीब लोगों की आवश्यकताऐं बहुत छोटी–छोटी होती हैं जबकि उनकी पहुँच वित्तिय संसाधनों तक नहीं होती। अतः लघु वित्त व्यवस्था के माध्यम से उनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। लघु वित्त के माध्यम से छोटे व सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के साथ–साथ भूमिहीन मजदूरों, पशुपालकों व मछली पालन करने वालों व अन्य कुटीर औद्योगिक गतिविधियों में लगे लोगों को सरलता से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

लघु वित्त प्रदान करनी वाली संस्थाऐं आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त ग्रामीणों को बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इस बचत पर भी ऋण सुविधा दी जाती है। इस प्रकार आसानी से ऋण प्राप्त होने के कारण ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सरकार के प्रयासों के चलते एवं ग्रामीण लोगों में फैली जागरूकता के कारण सूदखोरी प्रथा अब समाप्ति की और जा रही है। 1954 के सर्वे के अनुसार ग्रामीणों द्वारा लिए गए कुल ऋणों का 70 प्रतिशत ऋण स्थानीय सेठ–साहूकारों से लिया जाता था, लेकिन 1991 के सर्वे के अनुसार अब यह 18 प्रतिशत रह गया था और आजकल को सेठ–साहूकारी ऋण व्यवस्था बैंकों की लघु वित्तिय व्यवस्था से प्रतियोगिता करने में बिल्कुल हार मानती दिखाई पड़ती है।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

लघु ऋणों की ग्रामीणों के जीवन में भूमिका को देखते हुए यूएनओ ने वर्ष 2005 को अन्तर्राष्ट्रीय लघु वित्त वर्ष घोषित कर दिया है। हम सब जानते है कि भारत की ग्रामीण जनता अधिकतर कृषि पर आधारित है इसी को देखते हुए भारत में स्थापित वित्तिय संस्थाऐं भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के अनुकूल ही वित्तिय कार्यक्रम बनाती है। अगर भारत में इसकी कार्यक्रम शुरूआत को देखें तो पता चलता है कि सन् 1904 में ग्रामीण सहकारी बैंक के रूप में हुई सन् 1975 में भारत के रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की। ये क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैक की स्थापना की। ये क्षेत्रीय बैंक ग्रामीणों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं तथा इसके साथ उस क्षेत्र की छोटी –छोटी बचतों को एकत्रित करते है, यही छोटी–छोटी बचतें पूँजी का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होती हैं, जिससे ग्रामीणों का भविष्य सुनहरा बनने की उम्मीद होती है।

भारत में लघु वित्तिय संस्थाओं का विवरणः

राष्ट्रीय ग्रामीण तथा कृषि विकास बैंक

इस वित्तिय संस्था का पूरा नाम कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक है, जिसे अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप में नाबार्ड कहा जाता है इस बैंक की स्थापना 12 जुलाई, 1982 को संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा की गई यद्यपि विधिपूर्वक उद्घाटन 5 नवम्बर, 1982 को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा एक विशेष समारोह के दौरान किया गया। नाबार्ड के उद्देश्य –

1. एकीकृत ग्रामीण विकास को उद्देश्यपूर्ण दिशा प्रदान करना और इस पर ध्यान केन्द्रित करना।
2. सम्पूर्ण ग्रामीण ऋण व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करना।
3. छोटे उद्योगों, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों, शिल्पकारों और किसानों के लिए निवेश ऋण की व्यवस्था करना।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

4. ग्रामीण ऋण संस्थाओं के लिए अनुपूरक निधिकरण हेतु उपलब्धक के रूप में कार्य करना।
5. ग्रामीण ऋण संस्थाओं का समन्वय करना।
6. नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों आदि के स्टॉफ को अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाऐं प्रदान करता है।
7. कृषि और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित केन्द्रिय सरकार द्वारा अनुमोदन हुए मामलों में प्रत्येक ऋण प्रदान करता है।

अतः यह ग्रामीण लोगों को लघु ऋण उपलब्ध कराने हेतु देश की शीर्ष संस्था है। लघु वित्त की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार तथा अन्य वित्तिय एजेंसियों से वित्तिय सहायता प्राप्त करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकः

इसकी स्थापना 2 अक्टूबर, 1975 में भारत में ग्रामीण साख की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 26 सितम्बर, 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देशभर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की घोषणा की। 1975 को पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए।

1. माल्या (पश्चिम बंगाल में) में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना की गई – जिसे युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया कहा गया।
2. जयपुर (राजस्थान) में युनाईटेट कॉमशियल बैंक की स्थापना हुई
3. भिवानी (हरियाणा) – हरियाणा के भिवानी जिले में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना पंजाब नेशनल बैंक के नाम से हुई।
4. गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) – गोरखपुर के उत्तर प्रदेश शहर में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक – स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नाम से लघु वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

5. मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) – उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में भी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों को लघु वित्त पोषित करना है।

ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों, मजदूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को उधार एवं अन्य प्रकार की वित्तिय सुविधाऐं उपलब्ध कराना था। देश के सभी राज्यों में स्थापित इन बैंकों का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्रीय जनता को वित्त व ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इन बैंको के द्वारा लगभग 90 प्रतिशत फीसदी लोन ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों को ही दिया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य:

1. स्थानीय क्षेत्र के युवा वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराना।
2. ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिग सेवाओं का विस्तार करना।
3. शहरी मुद्रा बाजार से पुनर्वित के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की और ऋणों का प्रवाह बनाना।
4. लघु व कुटीर व्यवसायों के लिए लघु वित्त का पोषण करना।
5. ग्रामीण जनता को ऋण व अग्रिम प्रदान करना।
6. कृषकों को खाद–बीज के लिए लघु वित्त उपलब्ध कराना।
7. ग्रामीण गरीबों को ऋण आसानी से उपलब्ध कराना।

प्राथमिक साख समितियाँ:

स्थानीय लोगों की छोटी–छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कम से कम दस व्यक्ति मिलकर प्राथमिक साख समिति बना सकते हैं, इनके द्वारा कम से कम एक वर्ष अधिक से अधिक तीन वर्ष तक के लिए ऋण दिया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना:

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

इस योजना का प्रारम्भ 1998 में हुआ जिसका उद्देश्य कृषकों को अत्यन्त कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना था। इनके माध्यम से भारत में विभिन्न लघु वित्त कार्यक्रम चलाए जा रहे हें और विश्व स्तर तक इन कार्यक्रमों को सफलता मिली है। लघु वित्त कार्यक्रमों को सफलताओं को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण तथा कृषि विकास बैंक (Nabard) ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिकेंज कार्यक्रम का प्रारम्भ सन् 1992 में किया। बाद में इस स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम को 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण तथा तकनीकी जानकारी व्यवसायिक आधार के साथ उपलब्ध कराया जाता है।

ग्रामीण विकास में लघु वित्तः

लघु ऋणों के लिए चलाए गए वित्ति कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीणों की वित्तिय आवश्यकताऐं पूरी होने के साथ–साथ उन्हें रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए है। जिसके फलस्वरूप ग्रामीणों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अतः तथ्य को पुष्ट करने के लिए नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह जो वर्ष 2007 तक दस लाख समूह बनाने का लक्ष्य था यह लक्ष्य नाबार्ड ने 2004 में ही प्राप्त कर लिया। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम पूरे विश्व में सबसे तीव्र गति से फैलने वाला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की Growth rate नब्बे फीसदी है और ऋण भुगतान करने की दर 95 प्रतिशत है। ऋण अदायगी की उच्च दर लघु वित्त कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाती है।

लघु वित्त की ग्रामीणों के जीवन में भूमिकाः

1. लघु ऋण व वित्त व्यवस्था से उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
2. जीवन यापन करने हेतु रोजगार प्राप्त करना आसान हो गया है।
3. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ।
4. सेठ–साहूकारों वाली शूद प्रथा का अन्त हुआ।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

5. गरीब किसानों द्वारा खाद–बीज प्राप्त करना आसान हुआ।
6. स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा की उपलब्धता में लघु वित्त व्यवस्था बहुत सहायक सिद्ध हुई है।
7. शिक्षा, पीने का जल आदि मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध हो गई है।
8. अत्यधिक गरीब जनता की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लघु वित्त के कारण संभव हुआ है।
9. ग्रामीण क्षेत्र में बचतों को प्रोत्साहन भी लघु वित्त से संभव
10. लघु व कुटीर उद्योगों का उत्थान
11. बैंकिग सेवाओं का ज्ञान प्राप्त करना आसान

निष्कर्ष: संक्षिप्त रूप में यह कहा जा सकता है कि लघु ऋणों की ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों सूद प्रथा समाप्त होने की कगार पर है। विश्व स्तर पर भी इस तथ्य को स्वीकार लिया गया है कि गरीब ग्रामीणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तिय कार्यक्रम बहुत ही सहायक सिद्ध हुए है तथा गरीबी हटाने का यह एक प्रमुख हथियार है विभिन्न अध्ययनों के द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि प्राचीन समय में सेठ–साहूकारों से वित्त प्राप्त करने की दर 62 फीसदी थी। लेकिन लघु वित्त व्यवस्था के कारण यह अब 10 प्रतिशत के लगभग है। युनाईटेड नेशरल कमेटी 2005 के अनुसार लघु ऋण सेवाऐं स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें लघु ऋणों की वित्त व्यवस्था ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। लघु वित्तिय कार्यक्रम स्थानीय आधार पर सम्पन्न किए जाते है। अतः हम कह सकते है कि लघु वित्त व्यवस्था के द्वारा अभावग्रस्त लोगों की जरूरतों को पूरा कर उनके जीवन के स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है। लघु ऋण सेवाओं का आकार छोटा होता है अर्थात् ऋण की राशी बहुत छोटी होती है तथा ये सेवाऐं अधिकतर अत्यधिक गरीब लोगों को प्राप्त होती है।

सन्दर्भ सूची:

1. जैन एवं रवींचा, भारत का व्यवसायिक पर्यावरण
2. अमित कसंल, वाणिज्य पुस्तक, अरिहन्त पब्लिकेशन
3. रूद्रदत्त एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था
4. योजना पत्रिका, अक्टूबर 2013
5. वर्मा
6. पंचायती राज
7. प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका
8. स्वयं सेवी संगठन एवं ग्रामीण विकास
9. अविष्कार पब्लिसर